राजस्थान में फ्लोराइड्-युक्त दूषित जल

*348. **डा. प्रभा ठाकुर**: क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में उन जिलों की संख्या कितनी है जहां फ्लोराइड युक्त दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) इस प्रकार का जल पीने से कितने प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं; और

(ग) सरकार ने आम जनता को इन बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु क्या-क्या प्रावधान किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सी.पी. जोशी): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 33 जिलों में कुछ गांव भू-जल में अत्यधिक फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित हैं।

(ख) बिना किसी उचित पौष्टिक आहार के अत्यधिक फ्लोराइड के उपभोग से डेन्टल फ्लूरोसिस, स्केल्टल फ्लूरोसिस और/या नॉन-स्केल्टल फ्लूरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

(ग) भारत सरकार जल गुणवत्ता समस्याओं से प्रभावित बसावटों में पेयजल मुहैया कराने के राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ा हुआ वित्त-पोषण;

(ii) जल गुणवत्ता समस्यओं का समाधान करने के लिए संकेंद्रित वित्त-पोषण;

(iii) जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों को उनके पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम शुरू करना;

(iv) ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंडअलोन जल शुद्धिकरण प्रणाली लगाने की योजना शुरू करना;

(v) पेयजल में अत्यधिक फ्लोराइड से निपटने के उपायों के संबंध में जानकारी पुस्तिका तैयार करना और इसका वितरण करना;

(vi) पेयजल से अत्यधिक फ्लोराइड को दूर करने वाली प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार;

(vii) फ्लोरइड संबंधी मुद्दों पर जानकारी एवं प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन करना।

Fluoride contaminated water in Rajasthan

†*348. DR. PRABHA THAKUR: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of districts in Rajasthan where fluoride contaminated drinking water is being supplied;

(b) the types of the health-related problems the drinking of such water may cause; and

(c) the details of provision made by Government for clean drinking water to save common people from those diseases?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI C. P. JOSHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As reported by the State Government of Rajasthan, some villages in all the 33 districts of the State are affected with excess fluoride in ground water.

(b) Consumption of excess fluoride without appropriate nutritional intervention may lead to diseases like dental fluorosis, skeletal fluorosis and / or non-skeletal fluorosis.

(c) Government of India assists the States in their endevaour to provide potable water to habitations facing water quality problems. The steps taken, *inter alia* are:

(i) enhanced funding to meet drinking water needs;

(ii) focused funding for addressing water quality problems;

(iii) introduction of National Rural Drinking Water Quality Monitoring & Surveillance Programme to increase the awareness and to enable the rural communities to test quality of their drinking water sources;

(iv) launching a scheme to install standalone water purification systems in rural schools;

(v) preparation and distribution of literature on measures to deal with excess fluoride in drinking water;

(vi) dissemination of technology to remove excess fluoride from drinking water;

(vii) organization of workshops and seminars to impart training and knowledge on fluoride related issues.

डा. प्रभा ठाकुर: सर, मैंने विवरण पढ़ा है और सरकार ने माना है कि राजस्थान राज्य के सभी 33 जिलों में, जो बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, जहां कई गांव हैं, वे फ्लोराइड युक्त पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं। माननीय मंत्री जी स्वयं राजस्थान से आते हैं और वह राजस्थान की सभी समस्याओं से परिचित हैं। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से जो बीमारियां हो जाती हैं, वे बहुत ही गंभीर होती हैं, इनमें दांतों संबंधी डेन्टल फ्लूरोसिस और हड्डियों की बड़ी ही गंभीर बीमारियां हैं, जैसे स्केल्टल फ्लूरोसिस और नॉन-स्केल्टल फ्लूरोसिस हैं, ये बीमारियां इतनी गंभीर होती हैं कि इनमें समय से पहले दांत गिर जाते हैं और पीठ झुक जाती है।

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछ लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. प्रभा ठाकुर: सर, मैं प्रश्न पर ही आ रही हूं। इन सब स्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह कहा कि भारत सरकार इस समस्या से प्रभावित बसावटों में पेयजल मुहैया कराने के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। मैं यह जानना चाहती हूं कि चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान को इस समस्या से निपटने के लिए कितनी राशि का बजट अलॉकेशन किया गया है?

श्री सी.पी. जोशी: सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में पीने के पानी की अलग तरह की समस्या है, उस समस्या को address करने के लिए भारत सरकार राजस्थान सरकार को quality improvement करने के लिए बराबर पैसा दे रही है। 2006-07 में 206 करोड़ रुपए, 2007-08 में 292.43 करोड़ रुपए quality address करने के

लिए provide किए गए। 2009-10 के बजट के अंतर्गत भी भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को अभी लगभग 332.73 करोड़ रुपए release किए हैं।

राजस्थान में पीने के पानी की समस्या के लिए, खास तौर से फ्लोराइड के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 8,992 habitation फ्लोराइड से ग्रसित थे। पैसा देने के बाद quality improvement करने के बाद लगभग 5,355 habitations को cover किया गया है। लेकिन, unfortunately पानी का स्तर नीचे जाने के कारण, राजस्थान सरकार ने आज के दिन रिपोर्ट किया है कि राजस्थान में 10,725 habitations ऐसे हैं, जहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी है। राजस्थान में पीने के पानी का स्तर नीचे जाने के कारण फ्लोराइड की समस्या का निदान करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन पानी का स्तर नीचे जाने से यह समस्या बढ़ती जा रही है। इसको address करने के लिए 11th Plan में हम यह कोशिश कर रहे हैं कि पैसा देने के pattern में बदलाव किया जाए और quality को address करने के लिए ज्यादा पैसा दिया जाए। मंत्रि-मंडल में इस संबंध में हम निश्चित तौर पर प्रस्ताव रखेंगे, जिससे इस संबंध में ज्यादा अच्छी तरह से काम हो सके।

डा. प्रभा ठाकुर: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना है कि निरंतर अकाल पड़ने के कारण भूजल स्तर नीचे जा रहा है और उससे यह फ्लोराइड समस्या ज्यादा होती जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि इस गंभीर समस्या को, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, देखते हुए क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि राजस्थान को पेयजल की दृष्टि से विशेष श्रेणी के राज्य दर्जा दिया जाए और विशेष आर्थिक पैकेज और सहायता दी जाए? क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है?

श्री सी.पी. जोशी: माननीय सभापति महोदय, भारत के अलग-अलग प्रदेशों को जो हम पैसा देते हैं, उसमें से लगभग 13.51% शेयर राजस्थान को मिलता है। अभी भी 2005 से लेकर 2009 तक 22,347 करोड़ में से राजस्थान को लगभग 3,019 करोड़ रुपए आबंटित हुए हैं। यह राशि पानी की quality को address करने के लिए भारत सरकार राजस्थान सरकार को दे रही है। अब हम जब 11th Plan में quality को address करने के लिए मंत्रि-मंडल में पैसे देने के pattern को बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस समस्या का कितना निदान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसे करने के बाद यह बात आएगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय भी राजस्थान से हैं, मैं भी राजस्थान से हूं। उनको भी सरकार में रहने का बहुत मौका मिला है, मुझे भी मौका मिला है। फ्लोराइड की समस्या से वे भली-भांति परिचित हैं, किन्तु जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि ज्यों-ज्यों *दवा की, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया।* उन्होंने प्रत्युत्तर में बताया कि जमीन का पानी का स्तर नीचे जा रहा है, इसलिए फ्लोराइड और बढ़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि एक ही हल कि पीने का शुद्ध पानी बाहर से सप्लाई किया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे कि आगामी पांच वर्षों में जितने, 10,000 से ऊपर गांव प्रभावित हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: वही कर रहा हूं, सर। उनमें शुद्ध पानी बाहर से लाकर देने के बाद अगले पांच सालों में कितने गांवों में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो जाएगा?

श्री सी.पी. जोशी: माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में as on today 90% पानी की स्कीम्स underground water पर निर्भर हैं। राजस्थान में लगभग 60% groundwater से हमारा जो पानी उपलब्ध है, उससे

पानी की सारी समस्या का निदान करने के लिए हमने स्कीम्स बना रखी है। माननीय सदस्य महोदय स्वयं जानते हैं, यहां हम कह रहे हैं कि बाहर से पानी लाकर हम समस्या का समाधान करा दें और वहां जब हम जाते हैं तो हम लोकल लोगों को कहते हैं कि यहां का पानी वहां नही जाना चाहिए। हम दो तरह की बात करना चाहते हैं, एक तरफ हम अपनी political बात को करने के लिए कहते है कि यहां का पानी वहां नही जाना चाहिए और दूसरी तरफ बाहर से पानी मंगाकर समस्या का समाधान करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम गांव के पानी को address करने के लिए, quality को improve करने के लिए, फ्लोराइड को contain करने के लिए, जो अलग-अलग techniques हैं, उनको यूज करके 11th Plan में कोशिश करेंगे कि पानी की समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो। जहां पर फ्लोराइड ज्यादा है, जहां इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है, वहां दूर से पानी लाने की स्कीम के बारे में भी सोचेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWER TO STARRED QUESTIONS

Appointment of directors in PSUs

*341. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many director level posts in various Public Sector Undertakings (PSUs) are lying vacant for over six months as on 31 March, 2009;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether Government would resort to campus recruitment of suitable candidates from the Indian Institutes of Management (IIMs) as private sector companies do and train them for director level position in due course;

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI VILASRAO DESHMUKH): (a) and (b) As per available information, only 23 Board level posts (6 posts of Chief Executive and 17 posts of functional Directors) were vacant for more than six months as on 31.3.2009. The major reasons for vacancies in Board level posts are selection of existing Board level incumbents to other Board level posts resulting in vacancies at short notice, creation of new Board level posts, resignation or non-extension of tenure of incumbent, etc.

(c) Central Public Sector Enterprises are already allowed to make Campus Recruitment at entry level posts of Management Trainees from reputed institutions like Indian Institute of Management. Director level positions of Central Public Sector Enterprises are filled up by the Government on the basis of the recommendations of Public Enterprises Selection Board.

(d) Does not arise.